



EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

As the broadcasting industry continues to evolve, the intersection of telecom and television has become more pronounced than ever. The Telecommunications Act, 2023, is set to redefine the regulatory framework for broadcasting services, ensuring modernization, compliance, and fair competition. India's television broadcasting sector has undergone a dramatic transformation—from a state-controlled monopoly to a thriving, competitive industry. Over the years, regulations have adapted to accommodate new technologies such as satellite TV, Direct-to-Home (DTH), Internet Protocol Television (IPTV), and digital cable systems.

The rise of Over-the-Top (OTT) platforms and the growing popularity of Free Dish services have intensified the challenges faced by traditional DTH and Multi-System Operators (MSOs). As subscription-based Pay-TV services struggle with declining viewership, industry players are rethinking strategies to stay relevant in a rapidly changing media ecosystem.

The regulatory status of OTT platforms remains a hotly debated issue in India. While traditional Distribution Platform Operators (DPOs) operate under stringent regulations, OTT services currently function outside such oversight. This regulatory gap has raised concerns over content standards, tariff structures, and the competitive imbalance between traditional broadcasters and digital streaming platforms.

A major industry development is on the horizon as Airtel and Tata Play move toward a landmark merger of their DTH businesses. This consolidation is expected to reshape the Indian broadcasting landscape, enhancing service capabilities and driving synergies in the highly competitive DTH sector.

From pioneering fibernetworks to driving OTT innovation, Sandeep Donde, Founder & MD of Microscan has been at the forefront of India's digital transformation for over two decades

Satellite broadband gets a boost with the new tie-ups. India's telecom companies Jio and Airtel are in a heated competition to secure a strategic partnership with SpaceX's Starlink, aiming to revolutionize broadband connectivity across the country.

(Manoj Kumar Madhavan)

जैसे-जैसे प्रसारण उद्योग विकसित होता जा रहा है, दूरसंचार और टेलीविजन का अंतरसंबंध पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। दूरसंचार अधिनियम 2023, आधुनिकीकरण, अनुपालन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए प्रसारण सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। भारत के टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में एक नाटकीय परिवर्तन आया है—एक राज्य नियंत्रित एकाधिकार से एक संपन्न, प्रतिस्पर्धी उद्योग में बदल गया है। पिछले कुछ वर्षों में, सैटेलाइट टीवी, डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) और डिजिटल केबल सिस्टम जैसी नयी तकनीकों को समायोजित करने के लिए नियमों को अनुकूलित किया गया है।

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के उदय और फ्री डिश सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता ने पारंपरिक डीटीएच और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। चूंकि स्वयंक्रियण आधारित पे टीवी सेवायें घटती हुई दर्शकों की संख्या से जूझ रही हैं, इसलिए उद्योग के खिलाड़ी तेजी से बदलते मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म की विनियामक स्थिति एक गरमागरम बहस का मुद्दा बनी हुई है। जबकि पारंपरिक वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) कड़े नियमों के तहत काम करते हैं, ओटीटी सेवायें वर्तमान में ऐसी निगरानी के बहार काम करती हैं। इस विनियामक अंतर ने सामग्री मानकों, टैरिफ संरचनाओं और पारंपरिक प्रसारकों और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन पर चिंतायें बढ़ा दी है।

एयरटेल और टाटा प्ले अपने डीटीएच व्यवसायों के ऐतिहासिक विलय की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उद्योग जगत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस विलय से भारतीय प्रसारण परिदृश्य में नयापन आने की उम्मीद है, जिससे सेवा क्षमतायें बढ़ेंगी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी डीटीएच क्षेत्र में तालमेल बढ़ेगा।

फाइबर नेटवर्क में अग्रणी भूमिका निभाने से लेकर ओटीटी इनोवेशन को आगे बढ़ाने तक, माइक्रोस्कैन के संस्थापक और एमडी संदीप डोंडे पिछले दो दशकों से भारत के डिजिटल परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं।

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को नये गठजोड़ से बढ़ावा मिलेगा। भारत की दूरसंचार कंपनियां जियो और एयरटेल, स्पेसएक्स के स्टारलिनिक के साथ रणनीतिक साझेदारी हासिल करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं, जिसका लक्ष्य पूरे देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में क्रांति लाना है।

(Manoj Kumar Madhavan)